जबलपुर गोंदिया छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना

4621. **श्री शरद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर-गोंदिया, गोंदिया-चांदा और नैनपुर-नागपुर नैरोगेज सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है ; और

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख). अलाभप्रद शाखा लाइन समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, 1972–73 में सतपुड़ा रेल प्रणाली के उत्तरी खण्ड के आमान-परिवर्तन के उद्देश्य से, जिसमें निम्नलिखित लाइनें सम्मिलित हैं, एक यातायात सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन इस परियोजना को अर्थक्षम नहीं पाया गया :

(I) परसिया-छिन्दवाड़ा-सिओनी-नैनपुर-मांडलाफोर्ट;

(II) जबलपुर नैनपु-रबालाघाट-गोंदिया तथा बालाघाट-कटंगी ; और

(III) छिन्दवाड़ा-नागपुर

जबलपुर-गोंदिया लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए एक नया सर्वेक्षण किया जा रहा है । गोंदिया-चांदा खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Connecting of Sidhi Town by a Train

4622. SHRI SURYA NARAIN SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal for connecting Sidhi town in Madhya Pradesh by any connecting train;

(b) whether any survey to this effect has been made; and

(c) if so, the details thereof and estimated cost for construction of the railway line?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c). No survey has been carried out so far for construction of a rail link connecting Sidhi Town in Madhya Pradesh, and it will not be possible to consider the proposal at present on account of the limited availability of resources.

निलम्बित कर्मचारियों के मामलों का निपटान

4623. **श्री राम नरेश कुशवाहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निलम्बित रेल कर्मचारियों के मामलों का फैसला करने के लिए कोई समय सीमा नियत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो समय सीमा क्या है ;

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे के कितने कर्मचारियों के मामले निर्धारित समय पूरा हो जाने के उपरान्त भी निलम्बित है ; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) निलम्बन को रद्द करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है । फिर भी, वर्तमान नियमों में यह व्यवस्था है कि निलम्बन की अवधि को घटाकर कम से कम किया जाए ।

Allegations of Rigging of 1972 Assembly Poll

4624. SHRI MUKUNDA MANDAL: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Congress-opposed political parties in West Bengal brought allegations of wholesale rigging of the 1972 Assembly Poll, against the erstwhile Central Government and West Bengal State Government led by the Congress;

(b) if so, the nature of the allegations; and

(c) whether the Government will consider to constitute a high-powered body under the Commission of Inquiry Act to probe into the allegations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NARSINGH YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) The allegation was that the whole election in West Bengal was rigged as a result of a preplanned conspiracy engineered at the highest level and that manipulation of ballot papers and ballot boxes and fraud during counting had in a large number of constituencies come to light. It was also alleged that in some cases defeated candidates were declared elected.

(c) Neither the Constitution nor the election law provides for such a course of action. Article 329(b) of the Constitution provides that "no election to either House of Parliament or to the Legislature of a State shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under any law made by the appropriate Legislature."